भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 84

02 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

वार्षिक कार्बन उत्सर्जन

84. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूरोपीय संघ के देशों और उत्तरी अमेरिका की तुलना में भारत में इस्पात क्षेत्र द्वारा उत्पादित वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के बारे में अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पेरिस समझौते के अनुरूप इस्पात उद्योगों द्वारा होने वाले उत्सर्जन के पर्यावरणीय प्रभाव को समझने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लक्ष्य एक कार्बन क्रेडिट बाजार प्रणाली आरंभ करना है, जो एक कंपनी को पिछले उत्पादन के साथ-साथ अपेक्षित उत्पादन और सीमित कार्बन उत्सर्जन क्षमता के आधार पर अनुमति देता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में इस्पात क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने के लिए देश के भीतर विकसित किए जा रहे और अन्य देशों से आयात किए जा रहे प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) जी, हां। यूरोपीय संघ (ईयू) एवं उत्तरी अमेरिका के इस्पात उद्योग की तुलना में भारतीय इस्पात क्षेत्र की उत्सर्जन तीव्रता उच्चतर है। भारतीय इस्पात उद्योग की उच्चतर उत्सर्जन तीव्रता के कारण हैं:

- तकनीकी-आर्थिक कारणों की वजह से यूरोपीय संघ एवं उत्तरी अमेरिका के ब्लास्ट फर्नेस में 100% प्रीपेयर्ड बर्डन के प्रयोग की तुलना में प्रीपेयर्ड बर्डन (पेलेट एवं सिंटर) का कम प्रयोग।
- प्रतिस्पर्धी दरों पर इस्पात स्क्रैप की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यूरोपीय संघ एवं उत्तरी अमेरिका के इस्पात उद्योग की तुलना में उनके इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) में इस्पात स्क्रैप के प्रयोग की कम प्रतिशतता।

(ख) भारतीय इस्पात क्षेत्र की वर्तमान सीओ$_2$ उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन क्रूड इस्पात का लगभग 2.55-2.60 टन सीओ$_2$ है जो 2005 में प्रति टन क्रूड इस्पात के करीब 3.1 टन सीओ$_2$ से कम हुआ है। देश के ऊर्जा एवं औद्योगिक क्षेत्र से उच्च उत्सर्जन को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, सरकार उत्सर्जन को कम करने और पेरिस समझौते के तहत देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्न-कार्बन मार्ग का प्रबलता से अनुसरण करने हेतु कार्बन मार्केट का विकास कर रही है।

(ग) ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से वर्तमान अवसंरचना एवं कार्बन मार्केट के प्रचालन को समझने के लिए राष्ट्रीय कार्बन मार्केट पर मसौदा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट दस्तावेज में भारत में स्वैच्छिक कार्बन मार्केट के सृजन हेतु कार्यप्रणाली का प्रस्ताव दिया गया है और बाजार के अवरोधों को सुलझाने के लिए सुझाव दिया गया है।

(घ) इस्पात क्षेत्र में आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजनाओं में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है।

इस्पात क्षेत्र को लौह एवं इस्पात विनिर्माण प्रक्रियाओं में हरित हाइड्रोजन के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन में एक महत्वपूर्ण हितधारक भी बनाया गया है। इस पहल के अंतर्गत (डीआरआई) उत्पादन में हरित हाइड्रोजन के प्रयोग की व्यवहार्यता की संभावना तलाशने के लिए सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के अंतर्गत दो प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

****